जज जे.एस. सेखों

राम काली, -पुटिशर। बनाम उजला और एक और, -सोन्सेंटेंट्स।

1987 का सिविल रिवीजन नंबर 599

31 अगस्त, 1988।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का v) O. 1, RI। 10-एप्लिकेशन को एक पार्टी-अवधारणा के रूप में निहित किया जा रहा है जिसके तहत कहा जा सकता है कि आवेदन की अनुमति दी जा सकती है।

आयोजित, कि ऑर्डर 1 के उप-पीएआरए (2) के प्रावधानों के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 10, 1908, एक व्यक्ति को दो आकस्मिकताओं में सूट के लिए एक पार्टी के रूप में जोड़ा जा सकता है, पहला यह है कि वह उसे होना चाहिए शामिल हो गए हैं और ऐसा शामिल नहीं है, अर्थात, जब वह आवश्यक पार्टी है, या, जब उनकी उपस्थिति के बिना सूट में प्रश्न प्रभावी रूप से और पूरी तरह से स्थगित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन एक पार्टी को जोड़ने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह एक बचाएगा तीसरा व्यक्ति एक संपार्श्विक मामले के स्थगन की मांग के लिए एक अलग सूट का खर्च और परेशान करना, जो कि सूट के तहत सीधे और उप-स्थिर रूप से नहीं था, जिसमें वह घुसपैठ की तलाश करता है। बहुत ही तथ्य यह है कि सूट में निष्कर्ष हस्तक्षेप करने वाले को प्रभावित करेंगे, इस तरह के व्यक्ति को एक पार्टी के रूप में बताने के लिए कोई आधार नहीं है।

(पैरा ५)

आयोजित, कि विवाद में विवादित भूमि के मालिक-जहाज का निर्धारण शामिल है, जो शुरू में प्रतिवादी से संबंधित था, लेकिन उसने 19 अप्रैल, 1977 को सिविल कोर्ट के एक डिक्री के माध्यम से अपने ग्रैंड-सोन के पक्ष में इसे स्थानांतरित कर दिया। कोई विवाद नहीं है। वर्तमान मामले में, विवाद इस तथ्य से संबंधित है कि क्या प्रतिवादी ने देश को विवाद में अपने भव्य-बेटे को पहले स्थानांतरित कर दिया था या उसने

अपनी भव्य-बेटी, सादे-सादे को वर्तमान मामले में एक ही स्थानांतरित कर दिया है। इस प्रकार, ग्रैंड-सोन की विधवा को फंसाने के बिना उपरोक्त संदर्भित विवाद को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से तय नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी ने केवल इस तथ्य को जो अपने ग्रैंड-बेटे की विधवा के खिलाफ घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया था, वह ज्यादा परिणाम नहीं है।

(पारस ५ और १३)

श्री आर। एल। संख्ला, सब जज 1st क्लास हंसी के आदेश के संशोधन के लिए धारा 115 सीपीसी के तहत याचिका, 26 नवंबर, 1986 को दिनांक 26 नवंबर, 1986 को आवेदक के आवेदन की अनुमति नहीं दी गई और अब 10 वीं पर आने वाला मामला दिसंबर, 1986 प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन पर विचार के लिए,

याचिकाकर्ता के लिए सी। बी। गोएल, अधिवक्ता। एस। एन। सिंगल, एडवोकेट, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

उत्तरी नंबर 1 के लिए सुरिंदर गांधी, अधिवक्ता।

प्रलय

जज जय सिंह सेखोन

(1) राम काली, वादी, ने 26 नवंबर, 1986 को अधीनस्थ न्यायाधीश। वर्ग, हनी के आदेश के खिलाफ इस संशोधन याचिका का निर्देशन किया है, जिससे एमएसटी के निहितार्थ की अनुमति मिली। MST द्वारा दायर सूट में एक प्रतिवादी के रूप में संग्राह। राम काली, याचिकाकर्ता, अपने ग्रैंड फादर उजाला के खिलाफ।

(२) संक्षेप में कहा गया है, तथ्य यह है कि एमएसटी है। याचिकाकर्ता, राम काली ने अपने ग्रैंड-फादर उजाला के खिलाफ घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि वह इस आशय की है कि वह परिवार के निपटान के आधार पर गांव घिरई, तहसील हंस में 104 कनाल सीटूट-एड को मापने वाली भूमि का मालिक है और प्रतिवादी है विवाद में भूमि के साथ कोई चिंता नहीं है, इसके अलावा वह अपने पक्ष में स्वीकृत भूमि के

उत्परिवर्तन को प्राप्त करने का हकदार है। उक्त सूट में, उजला उजाला प्रतिवादी ने वादी के दावे को स्वीकार किया, 11 सितंबर, 1984 को अपने बयान को दिनांकित किया। इस सूट की पेंडेंसी के दौरान, एमएसटी। रंधिर की संतरो विधवा उजाला के एकमात्र भव्य-पुत्र ने एक आवेदन दायर किया। एक पार्टी के रूप में उसे बताने के लिए कि एक पारिवारिक बस्ती के माध्यम से, पूर्वोक्त उजला ने पहले ही विवाद में संपत्ति को अपने एकमात्र भव्य-पुत्र रंधिर को हस्तांतरित कर दिया था, 20 मई, 1977 को सिविल सिविल सूट ने फैसला किया। उसने झूठे और आधारहीन सूट का भी उल्लेख किया विवाद में संपत्ति को अलग करने और उसके पक्ष में स्वीकृत उत्परिवर्तन प्राप्त करने के लिए उसे अपने पति की मृत्यु के बाद उपरोक्त उजाला द्वारा दायर

किया गया। इस एप्लिकेशन को MST द्वारा विरोध किया गया था। राम काली वादी उस एमएसटी से इनकार करके। सैंट्रो रंधिर की विधवा है, या उजाला और पूर्वोक्त रणधीर के बीच पहले का समझौता। यह भी आरोप लगाया गया था कि पिछले डिक्री दिनांक 20 मई, 1977 को धोखाधड़ी और गलत प्रतिनिधित्व के आधार पर केवल एक पेपर लेनदेन है।

(३) सीखा अधीनस्थ न्यायाधीश, हालांकि, इस याचिका को को निहित करने की अनुमति देता है। mst सैंट्रो ने कहा कि वह पार्टियों के बीच विवाद को प्रभावी ढंग से स्थगित करने के लिए एक आवश्यक पार्टी है।

(४) श्री सी। बी। गोएल, ने याचिकाकर्ता के लिए वकील सीखा, बनार्सी दास दुर्गा परशद बनाम पन्ना लाल राम रिचपल ओसवाल और अन्य (१) (१), हिसर वी। म्यूनिसिपलिटी हिसार के बिमला देवी के माध्यम से इसके माध्यम से इस अदालत के निष्कर्षों पर भरोसा करके, इसके माध्यम से प्रशासक (2), नायब सिंह और एक अन्य वी। सदा राम और अन्य (3) और बारा हनुमान मंदिर दुर्गियन, अमृतसर बनाम गुरबैक्स लाल मल्होत्रा और अन्य (4), ने कहा कि श्रीमती के खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया था। सैंट्रो, वह न तो एक आवश्यक पार्टी थी और न ही उसकी उपस्थिति को प्रभावी ढंग से adjudi के लिए आवश्यक था, सूट में विवाद का उद्धरण। श्री सुरिंदर गांधी, उत्तरदाता नंबर 1 के लिए उपस्थित होने वाले वकील ने याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील के दृष्टिकोण का भी

समर्थन किया। उन्होंने वासुदेव और। नहवेलकर बनाम विष्णु अटमारम गौड और एक अन्य (5) में निष्कर्षों पर निर्भरता रखकर अपने तर्कों को और अधिक बताया। दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए वकील सीखा श्री एस। एन। सिंगल ने रज़िया बेकुम बनाम साहबजादी अनवर बेगम और अन्य (6) में सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों पर भरोसा करके ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों का समर्थन किया, साथ ही, साथ ही (6), गोकल चंद और अन्य वी। पुराण और अन्य (7) में इस अदालत के रूप में। उन्होंने बनारसी दास के मामले (सुप्रा) में इस अदालत के निष्कर्षों पर भी निर्भरता रखी, जो याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा भरोसा किया गया था।

(५) ऑर्डर १ के उप-पीएआरए (२) के प्रावधानों के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम १०, एक व्यक्ति को दो आकस्मिकताओं में सूट के लिए एक पार्टी के रूप में जोड़ा जा सकता है, पहला यह है कि वह होना चाहिए था शामिल हो गया और ऐसा शामिल नहीं है, अर्थात जब वह आवश्यक पार्टी है, या, जब उसकी उपस्थिति के बिना सूट में प्रश्न प्रभाव नहीं हो सकते हैं और पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है, लेकिन एक पार्टी को जोड़ने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह एक तीसरे व्यक्ति को एक संपार्श्विक मामले के अधिनिर्णय की मांग के लिए एक अलग सूट के खर्च और परेशान करने से बचाएगा, जो कि सीधे और पर्याप्त रूप से सूट के तहत इस मुद्दे में नहीं था। जिसे वह घुसपैठ करना चाहता है। बहुत तथ्य यह है कि सूट में निष्कर्ष अंतर्गर्भाशयी अंतराल को प्रभावित करेंगे, इस तरह के व्यक्ति को एक पार्टी के रूप में निहित करने के लिए भी कोई अच्छा आधार नहीं है। यह दृश्य इस न्यायालय के आर। एस। सरकार के निष्कर्षों से समर्थन पाता है, इस न्यायालय के जे। यह उस मामले में आगे आयोजित किया गया था कि वादी डोमिनस लिटस यानी

सूट के मास्टर है और वह उस व्यक्ति के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहता है और जिसके खिलाफ वह किसी राहत का दावा नहीं करता है। उपरोक्त संदर्भित मामले का अनुपात वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट के कॉन-क्लूशन का समर्थन करता है, क्योंकि इसमें विवादित भूमि के स्वामित्व का निर्धारण

शामिल है जो शुरू में उजाला, प्रतिवादी से संबंधित था, लेकिन उन्होंने 19 अप्रैल, 1977 को सिविल कोर्ट के एक डिक्री के माध्यम से अपने ग्रैंड-बेटे रणधीर के पक्ष में इसे स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार, उजाला अपने ग्रैंड-बेटी राम काली को उसी संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सका। जैसा कि वह वर्तमान मामले में ऐसा करने की कोशिश कर रहा है।

(६) बिमला देवी के मामले (सुप्रा) में याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा भरोसा किया गया था, विवाद में संपत्ति को ध्वस्त करने से नगरपालिका को रोकना एक निषेधाज्ञा देने से संबंधित विवाद, लेकिन उस संपत्ति का एक हिस्सा हरियाणा राज्य का था । इन परिस्थितियों में, यह आयोजित किया गया था कि हरियाणा राज्य एक आवश्यक पार्टी नहीं थी क्योंकि इसके खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया था।

(7) नायब सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के निष्कर्ष भी हाथ में मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हैं, क्योंकि इसमें विवादित भूखंडों के हस्तांतरण से संबंधित विवाद और बिक्री कर्मों और आदेश के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने शियो राम को नायब सिंह और बलदेव सिंह वादी के दूसरे भाई की अनुमति दी, इस तथ्य को देखते हुए कि वह न तो उक्त बिक्री विलेख के लिए एक पार्टी थी और न ही यह कहा जा सकता है कि विवाद को प्रभावी ढंग से तय नहीं किया जा सकता है बिना उसे इस तरह से फंसाए।

(8) बारा हनुमान के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के निष्कर्षों के बजाय वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों का समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें यह भी माना गया था कि गुर तकशद ट्रस्ट के वास्तविक कब्जे और प्रबंधन में हैं, एक आवश्यक पार्टी थी, भले ही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत मंजूरी देने के दौरान अधिवक्ता जनरल को एक आवश्यक पार्टी नहीं थी।

(९) अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त गोवा के निष्कर्ष, वासुदेव आर। नहवेलकर के मामले (सुप्रा) में भी हाथ में मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं हैं, जैसा कि मोचन के लिए एक सूट में, पार्टी के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई थी जो पार्टी के खिलाफ नहीं मांगी गई थी। खुद को बाद में प्रतिवादी के रूप में निहित करने की मांग की।

(१०) दूसरी ओर, रज़िया बेगम के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने पति और

पत्नी के रूप में पार्टियों की स्थिति की घोषणा के लिए एक सूट में आयोजित किया था, एक ही व्यक्ति की पत्नी का दावा करने वाला एक अन्य व्यक्ति एक आवश्यक पार्टी है, लेकिन में इस तरह के व्यक्ति को संपत्ति से संबंधित सूट का प्रत्यक्ष हित होना चाहिए, जैसा कि मुकदमेबाजी के विषय-वस्तु में वाणिज्यिक हित से अलग है। वर्तमान मामले में, एमएसटी भी। सैंट्रो की संपत्ति में प्रत्यक्ष रुचि थी, विवाद में अपने पति से बाद की मृत्यु के बाद भी उसे विरासत में मिला था।

(11) यह मानते हुए कि विवाद अनिवार्य रूप से एक गज़ी की पीड़ा

से संबंधित है और इस मामले के प्रभावशाली और पूर्ण स्थगन के लिए, गज़ी की संपत्ति के लिए एक और उत्तराधिकारी को अच्छी तरह से उचित ठहराया गया था।

(१२) इस न्यायालय का निर्णय (भागवंती बनाम गुरमीत कौर और अन्य) (8), वर्तमान मामले के लैक्ट्स के लिए भी आकर्षित नहीं है, क्योंकि इसमें एक पार्टी से संबंधित विवाद को मोचन के लिए एक सूट में शामिल किया गया है। गिरवी रखी गई भूमि जिसमें उस पार्टी से कोई राहत नहीं मारी गई थी।

(१३) इस बात का कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामले में, विवाद इस तथ्य से संबंधित है कि क्या उजाला ने भूमि को अपने भव्य-पुत्र रंधिर को पहले ही डिस-प्यूट में स्थानांतरित कर दिया था या उसने अपने ग्रैंड-बेटी एमएसटी में संत स्थानांतरित कर दिया था। राम काली, वर्तमान में वादी। इस प्रकार, पूर्वोक्त रणधीर की विधवा को निहित किए बिना, उपरोक्त संदर्भित विवाद को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से तय नहीं किया जा सकता है। केवल तथ्य यह है कि उजाला ने अपने ग्रैंड-बेटे रंधिर की विधवा के खिलाफ घोषणा के लिए एक बकवास दायर किया था, यह ज्यादा परिणाम नहीं है।

(१४) पूर्वगामी कारणों के लिए, इस पेटी में कोई योग्यता नहीं है, उसी में भी इसे खारिज कर दिया गया है, लेकिन पार्टियों को उनकी लागत सहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

जज ए एल बहरी

एस। डी। कॉलेज एजुकेशनल सोसाइटी, बरनाला, याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और एक अन्य, -सोनस। 1987 का सिविल संशोधन संख्या 3261

1 सितंबर, 1988।

भारत का संविधान, 1950-आर्ट्स। 14, 29 और 30-कोड सिविल प्रक्रिया (1908 का v) -Sec। 115-शैक्षिक संस्थान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस तरह के संस्थान या राज्य द्वारा जारी किए गए ऐसे संस्थान-निर्देशों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश

(1) A.I.R. 1969 Pb. & Hry. 57.

(2) 1983 H.R.R. 249

(3) 1985(2) C.L.J. 374.

(4) A.I.R. 1978 Pb. & Hry. 192.

(5) A.I.R. 1976 Goa 58.

(6) A.I.R. 1958 S.C. 886.

(7) 1978 P.L.R. 403

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा